भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 389 का उत्तर

गुजरात में नई रेल लाइनें बिछाना

389. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात सहित देश भर में नई रेल लाइनें बिछाने, मौजूदा रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण तथा उनके आमान परिवर्तन से संबंधित कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अनुमानित लागत और आवंटित तथा व्यय की गई निधि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

गुजरात में नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा के अतारांकित प्रश्न सं. 389 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, गुजरात सहित पूरी भारतीय रेल में, लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपये की लागत पर कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक, लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	11,527 करोड़ रु./वर्ष	-
2024-25	68,634 करोड़ रु.	लगभग 6 गुना

भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण की कमीशनिंग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	7,599 किलोमीटर	4.2 किलोमीटर प्रतिदिन	-
2014-24	31,180 किलोमीटर	8.54 किलोमीटर प्रतिदिन	2 गुना से अधिक

2023-24 में, भारतीय रेल में 5,309 कि.मी. खंड कमीशन किए गए हैं।

विद्युतीकरण के संबंध में, अब तक, भारतीय रेल पर 64,285 मार्ग किमी बड़ी लाइन नेटवर्क (97%) का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिसमें गुजरात में 3,933 किमी. शामिल है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, 21,145 मार्ग किमी का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें गुजरात में 2024 मार्ग किमी शामिल है।

गुजरात

गुजरात राज्य में रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे क्षेत्र द्वारा कवर की जाती हैं।

01.04.24 तक, गुजरात में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली 30826 करोड़ रु. की कुल लंबाई 2948 किलोमीटर की 42 परियोजनाएं (06 नई लाइन, 22 अमान परिवर्तन और 14 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 825 किलोमीटर लंबाई कमीशन हो चुकी है और मार्च, 2024 तक 9,335 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

गुजरात में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	589 करोड़ रुपये/वर्ष	-
2024-25	8,743 करोड़ रुपये	लगभग 14.84 गुना

इसके अलावा, 2009-14 और 2014-2024 के दौरान गुजरात राज्य में पूर्ण/आंशिक रूप से आने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कुल कमीशनिंग	औसत कमीशनिंग	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	660 कि.मी.	132 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	2,244 कि.मी.	224 कि.मी./वर्ष	1.69 गुना

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, गुजरात राज्य में कुल 567 कि.मी. कमीशन किया गया है।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन स्वीकृति, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्सेदारी का नियुक्ति, परियोजनाओं की प्राथमिकता, उल्लंघन करने वाली उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और भौगोलिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जलवायु परिस्थितियों

आदि के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या और ये सभी कारक परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते है।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। (i) निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना।

*****